



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2000/ज्येष्ठ 3, 1922

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2000/JYAISTHA 3, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच-शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2000

विषय : दक्षिण कोरिया तथा जर्मनी मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रीलोनीट्राइल बुटाडिन रबड़ (एन बी आर) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करना।

सं. 27/1/2000-डी जी ए डी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी ने (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए दक्षिण कोरिया तथा जर्मनी मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रीलोनीट्राइल बुटाडिन रबड़ (इसके बाद इसे एन बी आर कहा गया है) के पाटन पर 17.7.99 की अधिसूचना सं. 9/1/95 ए डी डी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। उक्त शुल्क अधिसूचना सं. 62-सीमाशुल्क दिनांक 30.7.97 द्वारा लगाया गया था।

1. **विचाराधीन उत्पाद:** विचाराधीन उत्पाद एक्रीलोनीट्राइल बुटाडिन रबड़ (एन बी आर) है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की अनुसूची I के सीमाशुल्क शीर्ष 4002.59 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली पर आधारित) सं. 4002.59.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकारी नहीं है।

2. **पाटनरोधी जांच का आरंभ:** सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत नियमों में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करें। इस समय दिनांक 17.7.97 की अधिसूचना सं. 9/1/95-ए.डी.डी. द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा की जरूरत है।

3. दिनांक 17.7.97 की अधिसूचना सं. 9/1/95-~~ए.डी.डी.~~ द्वारा जारी अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेते हुए, प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार दक्षिण कोरिया तथा जर्मनी मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रीलोनीट्राइल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को कायम रखने की आवश्यकता की समीक्षा के लिए एतद्वारा जांच शुरू करते हैं।
4. इस समीक्षा में 17.7.97 की अधिसूचना सं. 9/1/95-~~ए.डी.डी.~~ के सभी पहलू शामिल हैं।
5. जांच की अवधि: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक है।
6. मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज लि०, जो पहले मै० गुजरात अपार पोलीमर्स लि० के नाम से जानी जाती थी, को निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली उपर्युक्त अधिसूचना में घरेलू उद्योग के रूप में माना गया था। प्राधिकारी उक्त नियमों के अनुसार मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज लि० को घरेलू उद्योग के रूप में मानने का प्रस्ताव करते हैं।
7. सूचना प्रस्तुत करना: जिन निर्यातकों और आयातकों के सम्बद्ध होने की जानकारी है, उन्हें तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है ताकि वे संबंधित आवश्यक सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से प्रस्तुत कर सकें। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी जो मौजूदा जांच में भाग लेने की इच्छुक हो, निम्नलिखित को लिख सकती है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

(पाटनरोधी प्रभाग)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कमरा नं. 243

उद्योग भवन, नई दिल्ली

8. समय-सीमा: इस समीक्षा से संबंधित सभी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा उक्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष रिकार्ड कर सकते हैं।
9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण: नियम 6(7) के अनुसार कोई भी संबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

10. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकता है।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2000

Sub: - Initiation of review of anti-dumping duty imposed on Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from South Korea and Germany.

No. 27/1/2000-DGAD.— The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 notified final findings vide notification No.9/1/95-ADD on 17.7.99 dumping of Acrylonitrile Butadiene Rubber (herein after referred to as NBR) originating in or exported from South Korea and Germany. The duty was imposed vide notification No. 62 – Customs dated 30.7.97.

1. **Product Under Consideration:** The product under consideration is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) is classified under custom heading 4002.59 of Schedule 1 of Indian Customs Tariff Act, 1995 and No.4002.59.00 under Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System). The classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present review.
2. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the rules made thereunder require the Authority to review, from time to time, the need for the continued imposition of definite Anti-Dumping Duty imposed by the Central Government. These recommendations made by the Authority vide notification No.9/1/95-ADD dated 17.7.97, need to be reviewed at this stage.
3. Having decided to review the final findings made vide notification 9/1/95-ADD dated 17.7.97, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty imposed on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from South Korea and Germany in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995.

4. This review covers all aspects of Notification No.9/1/95-ADD on 17.7.97.
5. **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 1999 to 31st March, 2000.
6. M/s Apar Industries Limited, earlier known as M/s Gujarat Apar Polymers Ltd. was considered as the domestic industry in the above-referred notification of imposition of definitive anti dumping duty. The Authority proposes to consider M/s Apar Industries Ltd. as the domestic industry in accordance with the Rules supra.
7. **Submission of information:** The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:-

**THE DESIGNATED AUTHORITY
(ANTI DUMPING DIVISION)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
ROOM NO. 243, UDYOG BHAVAN, NEW DELHI**

8. **Time Limit:** - All information relating to this review should be sent in writing so as reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.
9. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority